BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVIII | 31st October 2017 | No. 10

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर के 90वाँ वार्षिक समारोह में बोले माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान

• पुआल से इथेनॉल बनाने का पहला प्रोजेक्ट सुपौल में • अगली दिवाली तक पटना के घरों में शुरू होगी गैस की सप्लाई • पटना में खुलेंगे 12 सीएनजी स्टेशन • बिहार में इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ के सारे कंपोनेन्ट मौजूद

वार्षिक समारोह का उद्घाटन करते माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह। उनकी बांयी ओर क्रमशः माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी। दांयी ओर चैम्बर कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, माननीय नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा एवं निवर्त्तमान महामंत्री श्री शशि मोहन ।

चैम्बर का 90वॉ वार्षिक समारोह दिनांक 6 अक्टूबर 2017 को चैम्बर के सभागार में आयोजित हुआ। समारोह के उद्घाटनकर्ता माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस एवं कौशल विकास, उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान थे। माननीय उद्योग मंत्री, बिहार, श्री जय कुमार सिंह, माननीय नगर विकास मंत्री, श्री सुरेश कुमार शर्मा समारोह में बतौर विशिष्ठ अतिथि उपस्थित थे।

समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन माननीय तीनों मंत्री महोदय एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला योजना में बिहार की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत होनी चाहिए। उन्होंने माननीय पेट्रोलियम मंत्री से आग्रह किया कि हल्दिया जगदीशपुर गैस पाइप लाइन का विस्तार छपरा से गोपालगंज होते हुए बेतिया तक किया जाय।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं हैं, जो चल रहे हैं वे मध्यम व सूक्ष्म उद्योग हैं, लेकिन इनकी स्थिति भी संतोषजनक नहीं है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग आधारित उद्योगों की काफी संभावना है। बिहार में निवेश का माहौल भी है। बैंकों का नकारात्मक रुख उद्योगों के लिए चिंता का विषय है।

चैम्बर अध्यक्ष ने बिहार की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं की ओर माननीय केन्द्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए बिहार को विशेष प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

समारोह को संबोधित करते हुए माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि उद्योग के क्षेत्र में बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है लेकिन नयी सरकार के गठन के बाद केन्द्र एवं राज्य सरकार में एक गठबंधन की सरकार होने से इस क्षेत्र में तेजी से विकास की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि उद्यमी समाज के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने उद्यमियों से आग्रह किया कि वे स्वावलंबी बिहार बनाने में मदद को आगे आयें।

माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नयी सरकार ने राज्य में निवेश का वातावरण बढ़ाया है साथ ही आधारभूत संरचनाओं में बढ़ोत्तरी की है। बिहार निवेश की दृष्टि से बड़ा बाजार है। यहाँ विधि व्यवस्था की स्थिति भी ठीक है।

उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बिहार उद्योग के क्षेत्र में अभी भी पिछड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ निवेश का माहौल पिछले कुछ सालों से बना है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ बड़े उद्योग स्थापित होंगे।

माननीय उद्योग मंत्री ने आगे कहा कि बिहार में मानव संसाधन बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। कुल मिलाकर देखा जाये तो आने वाले दिनों में बड़ा बाजार दिख रहा है। सरकार एवं उद्यमी मिलकर रोजगार सृजन करेंगे। उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं में बैंक अपनी भूमिका नहीं दिखा रहे हैं। सरकारी योजनाएं तभी सफल होगी जब बैंक सहयोग देंगे। सरकार बैंकों पर लगातार दबाव बना रही है ताकि वे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को सकारात्मक सहयोग दें।

समारोह को संबोधित करते हुए माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पहली बार राज्य और केन्द्र में एक ही सरकार है। विकास को नई दिशा देने का जो काम है, उसमे एक नाम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और बिहार में श्री नीतीश कुमार व

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

आपने मुझमें जो विश्वास व्यक्त कर, व्यापार एवं उद्योग की शीर्ष संस्था बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पद का गुरुतर भार पुनः सौंपा है, इसके लिए में आप सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूँ। मैं आपके विश्वास को अक्षुण रखने की पूरी कोशिश करूँगा। परन्तु आपका सहयोग सदैव अपेक्षित है।

90वीं वार्षिकोत्सव का उद्घाटन श्री धर्मेन्द्र प्रधान माननीय केन्द्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता के कर कमलों द्वारा हुआ। श्री जय कुमार सिंह, माननीय मंत्री उद्योग सह-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार एवं श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार भी कृपापूर्वक इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे।

इस अवसर पर माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा वैसे सदस्यों को सम्मानित किया गया जिन्होंने चैम्बर के अनुरोध पर मुख्यमंत्री राहत कोष में सहृदयता से सहयोग राशि प्रदान की, वे हैं– 1. अल्केम लेबोरेटरीज लि. (10 लाख), 2. श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता (1 लाख), 3. श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल (1 लाख), 4. श्री रामा शंकर प्रसाद (1 लाख), 5. श्री विशाल टेकरीवाल (1 लाख), 6. चैम्बर ऑफ कॉमर्स चैरिटेवल ट्रस्ट, गया (5 लाख), 7. श्री संजय खेमका (1 लाख)। इसके अतिरिक्त कुछ सदस्यों ने भी एक लाख से कम के चेक प्रदान किये थे। मैं उन सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और साधुवाद देता हूँ।

इसी अवसर पर चैम्बर के वयोश्रेष्ठ सदस्य डॉ. बी. बी. वर्मा को सम्मानित किया गया। वार्षिकोत्सव के आयोजन को पूर्ण रूप से सफल बनाने हेतु आप सभी सदस्यो के प्रति आभारी हूँ।

दिनांक 21 अक्टूबर 2017 को चैम्बर प्रांगण में माननीय श्री गंगा प्रसाद जी, महामहिम राज्यपाल, मेघालय के अभिनन्दन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री गंगा प्रसाद जी, जो 1987 से चैम्बर के सदस्य रहे हैं, उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया है। संभवतः यह पहला अवसर है कि वैश्य समाज का कोई प्रतिनिधि राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया हो। चैम्बर के लिए वह ऐतिहासिक दिन था। उनका अभिनन्दन कर हम स्वयं गौरवान्वित हुए।

दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को चैम्बर प्रांगण में विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर नेत्र जाँच शिविर आयोजित किया गया था। डॉ. शशि मोहनका, निदेशक, श्री बाला जी नेत्रालय ने अपनी टीम के साथ करीब 150 लोगों के आँखों की जाँच की। इनमें करीब 15 लोगों की आँखों में मोतियाविन्द के रोगी पाये गये। ये वैसे लोग थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे और मोतियाविन्द का ऑपरेशन कराने में असमर्थ थे। चैम्बर ने उन 15 लोगों के मोतियाविन्द के ऑपरेशन, दवा, चश्मा आदि का पूरा खर्च वहन करने का निर्णय लिया।

दिनांक 22 अक्टूबर 2017 को चैम्बर के सौजन्य से श्री बालाजी नेत्रालय, नाला रोड, पटना में उन 15 चयनित लोगों के मोतियाविन्द का ऑपरेशन प्रसिद्ध नेत्र सर्जन डॉ. शशि मोहनका ने अपनी टीम के साथ किया।

इस शिविर का उद्घाटन माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के कर कमलों द्वारा हुआ। माननीय मंत्री जी ने चैम्बर द्वारा किये गये इस सामाजिक कल्याण के कार्य की सराहना की। इस अवसर पर माननीय विधायक श्री अरूण कुमार सिन्हा एवं श्री नीतिन नवीन जी भी सम्मिलित हुए।

चैम्बर की बैठकों और कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता हेतु हार्दिक धन्यवाद। आप अपनी समस्याएं एवं सुझाव हमें प्रेषित करते रहें ताकि हम तद्नुसार काम कर सकें।

आपका

पी0 के0 अग्रवाल

श्री सुशील कुमार मोदी जी हैं। भारत की प्रगति तबतक नहीं होगी जबतक बिहार की 12 करोड़ जनता का विकास नहीं होगा। उन्होनें कहा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ के लिए जो कम्पोनेन्ट चाहिए वह सब बिहार में मौजूद है। अभी कोई देर नहीं हुई है। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है, एक करोड़ पच्चीस लाख के पैकज में हमारे पास 21 हजार करोड़ रूपये हैं। बरौनी रिफाइनरी का एक्सटेंसन करना है। पेट्रोकैमिकल्स के उत्पादन पर जोर दिया गया है। यहाँ प्लास्टिक दाना का उत्पादन होना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा बाजार बिहार और उत्तर भारत से जुड़ा है।

श्री प्रधान ने आगे कहा कि यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट तथा पॉलिस्टर के लिए फाइबर निर्माण का काम होगा। भागलपुर के टेक्सटाइल का एक बड़ा बाजार है। उन्होंने कहा व्यवस्था बनाना हमारा काम है, परन्तु काम आप सभी उद्यमियों को करना होगा। बिहार की कुल राजस्व प्राप्ति 25 हजार करोड़ रूपये हैं। ऐसे में शराबबन्दी लागू कर 5 हजार करोड़ का घाटा उठाना भी एक बड़े ही हिम्मत का काम है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

माननीय केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पुआल से इथेनॉल बन सकता है। सुपौल में इससे सबंधित पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्लांट शीघ्र स्थापित कराने जा रहा हूँ। हम 500 टन प्रतिदिन की कैपेसिटी का प्लांट लगाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार अगर इस मौके को गंवाता है, तो यह एक ऐतिहासिक भूल होगी।

उन्होंने पटनावासियों के लिए नल से गैस सप्लाई के अपने पुराने वादे को दुहराते हुए कहा कि अगली दीपावली तक यह काम पूरा कर लिया जायगा। लोकल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। 12 सी एन जी स्टेशन होंगे, 2700 करोड़ का खर्च आयेगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी जगदीशपुर-हल्दीया गैस पाइप लाइन योजना, जो लगभग 204 किलोमीटर है, इसका काम शुरू हो गया है। बरौनी से नौबतपुर पाइप लाइन बिछाई जायेगी। अक्टूबर 2018 तक यह काम पूरा हो जायेगा, साथ ही पटना शहर में लोकल नेटवर्क बनेगा। जिसके तहत 1800 किलोमीटर में स्टील पाइप लगेगी। श्री प्रधान ने कहा कि बिहार में पहली रिफाइनरी बरौनी में लगी थी। उस समय बड़ी संख्या में उद्यमी इससे जुड़े थे, लेकिन अफसोस की बात है कि बरौनी में महज 9 लोग ही बचे हैं जो इस उद्योग से जुड़े हैं।

माननीय केन्द्रीय मंत्री ने चैम्बर अध्यक्ष से कहा कि आप 25 लोगों की एक सूची तैयार करें और हमारे खर्चे पर देश भर में लगे उद्योगों का भ्रमण करें और बताएँ कि ये उद्योग बिहार में कैसे और कहाँ स्थापित किये जा सकते हैं।

माननीय केन्द्रीय मंत्री ने चैम्बर द्वारा स्थापित नि:शुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित अर्चना कुमारी, शोभा श्रीवास्तव, प्रीति कुमारी तथा साधना कुमारी को मेमेन्टो एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जो प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार कर रही हैं या नौकरी कर रही हैं।

इस अवसर पर चैम्बर के अपील पर "मुख्यमंत्री राहत कोष" के लिए माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह को चेक सौंपा गया। जिनमें एलकेम लेबोरेटरीज लि. के श्री सुधीर कुमार (10 लाख), श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता (1 लाख), श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल (1 लाख), श्री रामा शंकर प्रसाद (1 लाख), श्री विशाल टेकरीवाल (1 लाख), चैम्बर ऑफ कॉमर्स चैरिटेबल

ट्रस्ट, गया (5 लाख) के डॉ. कौशलेन्द्र प्रताप थे। श्री संजय कुमार खेमका की अनुपस्थिति में उनका एक लाख का चेक चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने माननीय उद्योग मंत्री को सौंपा।

एक लाख से उपर के चेक प्रदान करने वाले सदस्यों को चैम्बर द्वारा तैयार बुद्ध की प्रतिमा का मोमेन्टो एवं अंगवस्त्रम् माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री के हाथों प्रदान कर सम्मानित भी किया गया।

कुछ सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख से कम के चेक भी प्राप्त हुए थे उसे भी अध्यक्ष महोदय ने माननीय उद्योग मंत्री को सौंपा।

इसी अवसर पर चैम्बर के वयोश्रेष्ठ सदस्य डॉ. बी. बी. वर्मा. को माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा अंगवस्त्रम् प्रदान कर सम्मनित भी किया गया।

माननीय मंत्रियों को इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने चैम्बर का मेमेन्टों एवं अंगवस्त्रम् प्रदान कर सम्मानित भी किया।

समारोह के प्रारंभ से पूर्व माननीय केन्द्रीय मंत्री ने एवं माननीय उद्योग मंत्री ने चैम्बर द्वारा स्थापित एवं संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन किया और यहाँ चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यों को भी देखा। माननीय केन्द्रीय मंत्री ने चैम्बर द्वारा चलाये जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यों को सराहनीय एवं अनुकरणीय बताया।

समारोह में महापौर श्रीमती सीता साहू, विभिन्न बैंकों एवं संस्थानों के वरीय अधिकारीगण, प्रेस बन्धुगण एवं चैम्बर के सदस्यगण काफी संख्या में उपस्थित थे। समारोह का संचालन उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन पूर्व महामंत्री श्री शशि मोहन ने किया। धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात समारोह समाप्त हुआ।

90वाँ वार्षिक समारोह की झलकियाँ

चैम्बर द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के सिलाई प्रशिक्षण का अवलोकन करते माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं निवर्तमान महामंत्री श्री शशि मोहन एवं अन्य ।

कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के कम्प्युटर प्रशिक्षण का अवलोकन करते माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं निवर्तमान महामंत्री श्री शशि मोहन एवं अन्य ।

कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान एवं माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह को तुलसी का पौधा भेंट कर अभिनन्दन करती प्रशिक्षण केन्द्र की समन्वयक डॉ० श्रीमती गीता जैन। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं अन्य।

माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान का अभिवादन करती प्रशिक्षण केन्द्र की प्रशिक्षु महिलाएं।

समारोह में मंचासीन दायें से बांये माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह, माननीय नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा एवं निवर्त्तमान महामंत्री श्री शशि मोहन।

माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

माननीय नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर साथ में निवर्त्तमान महामंत्री श्री शशि मोहन।

माननीय महापौर श्रीमती सीता साहू को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में निवर्त्तमान महामंत्री श्री शशि मोहन।

समारोह में स्वागत् उद्बोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं मंचासीन माननीय मंत्रीगण एवं चैम्बर के पदाधिकारीगण।

समारोह को सम्बोधित करते माननीय नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा।

समारोह को सम्बोधित करते माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह।

सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण एवं सदस्यगण।

समारोह को सम्बोधित करते माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान।

माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान से विचार-विमर्श करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

मंचासीन (बाँये से दाँयें) माननीया महापौर श्रीमती सीता साहू, निवर्त्तमान महामंत्री श्री शशि मोहन, माननीय नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह, माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

चैम्बर के वयोश्रेष्ठ सदस्य डॉ० बी० बी० वर्मा को चैम्बर में उनके योगदान हेतु अंग वस्त्रम् से सम्मानित करते माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान।

माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान को चैम्बर का मेमेन्टो देकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं अन्य।

चैम्बर द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित महिला, जो अपना रोजगार कर रही है, को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र एवं मेमेन्टों प्रदान कर सम्मानित करते माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

चैम्बर द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षित महिला, जिसे नौकरी मिल गयी है, को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र एवं मेमेन्टों प्रदान कर सम्मानित करते माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

माननीय उद्योग मंत्री को चैम्बर का मेमेन्टों देकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ।

माननीय नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा को चैम्बर का मेमेन्टो देकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

चैम्बर के अपील पर "मुख्यमंत्री राहत कोष" हेतु चेक सौंपते सदस्यगण एवं चैम्बर द्वारा उनका सम्मान

चैम्बर के अपील पर ''मुख्यमंत्री राहत कोष'' हेतु माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह को चेक सौंपते एलकेम लेबोरेटरीज लि० के प्रतिनिधि श्री सुधीर कुमार।

"मुख्यमंत्री राहत कोष" हेतु चेक प्रदान करने वाले एलकेम लेबोरेटरीज लि० के श्री सुधीर कुमार को चैम्बर का मेमेन्टों प्रदान कर सम्मानित करते माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान।

चैम्बर के अपील पर ''मुख्यमंत्री राहत कोष'' हेतु माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह को चेक सौंपते श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता।

''मुख्यमंत्री राहत कोष'' हेतु चेक प्रदान करने वाले श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता को चैम्बर का मेमेन्टों प्रदान कर सम्मानित करते माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान।

चैम्बर के अपील पर ''मुख्यमंत्री राहत कोष'' हेतु माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह को चेक सौंपते चैम्बर ऑफ कॉमर्स चैरिटेबल ट्रष्ट, गया के प्रतिनिधि डॉ० कौशलेन्द्र प्रताप।

''मुख्यमंत्री राहत कोष'' हेतु चेक देने वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स चैरिटेबल ट्रस्ट, गया के प्रतिनिधि डॉ० कौशलेन्द्र प्रताप को चैम्बर का मेमेन्टों प्रदान कर सम्मानित करते माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान।

चैम्बर के अपील पर ''मुख्यमंत्री राहत कोष'' हेतु माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह को चेक सौंपते श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल।

''मुख्यमंत्री राहत कोष'' हेतु चेक प्रदान करने वाले श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल को चैम्बर का मेमेन्टों प्रदान कर सम्मानित करते माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान।

चैम्बर के अपील पर ''मुख्यमंत्री राहत कोष'' हेतु माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह को चेक सौंपते श्री रामा शंकर प्रसाद।

''मुख्यमंत्री राहत कोष'' हेतु चेक देने वाले श्री रामा शंकर प्रसाद को चैम्बर का मेमेन्टों प्रदान कर सम्मानित करते माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान।

चैम्बर के अपील पर ''मुख्यमंत्री राहत कोष'' हेतु माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह को चेक सौंपते श्री विशाल टेकरीवाल।

चैम्बर के अपील पर ''मुख्यमंत्री राहत कोष'' हेतु श्री संजय कुमार खेमका से प्राप्त चेक उनकी अनुपस्थिति में, माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह को चेक सौंपते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल।

मंचासीन बाँये से दाँये निवर्त्तमान महामंत्री श्री शशि मोहन, माननीय नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह, माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी। पीछे ''मुख्यमंत्री राहत कोष'' में चेक समर्पित करने वाले सम्मानित सदस्यगण।

चैम्बर के अपील पर ''मुख्यमंत्री राहत कोष'' में निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपनी सहयोग राशि प्रदान की है। चैम्बर उन सदस्यों के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद एवं साधुवाद देता है तथा उनके प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त करता है :

1. श्री राजा बाबू गुप्ता
2. श्री दिलजीत खन्ना
3. श्री गिरिधारी लाल सराफ
4. श्री जुगल किशोर झुनझुनवाला
5. श्री प्रदीप जैन
6. श्री अग्रवाल यशपाल

90वीं वार्षिक आम सभा में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने पी. के. अग्रवाल

आठवीं बार अध्यक्ष बनने वाले चैम्बर के दूसरे सदस्य, अमित मुखर्जी बने महामंत्री

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की कमान फिर एक बार श्री पी. के. अग्रवाल को सौंपी गई है। दिनांक 26.9.2017 को हुई 90वीं वार्षिक आमसभा में वे लगातार दूसरी बार सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हुए। बतौर अध्यक्ष यह उनका आठवां कार्यकाल होगा। श्री एन. के. ठाकुर और मुकेश कुमार जैन दोबारा उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। विशाल टेकरीवाल को भी कोषाध्यक्ष पद के लिए दोबारा जिम्मेदारी मिली है। महामंत्री के रूप में अमित मुखर्जी नया चेहरा होंगे। वे शशि मोहन का स्थान लेंगे।

नई कार्यकारिणी समिति में सावल राम डोलिया, सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा,

वार्षिक आम सभा में मंचासीन (बाँयें से) नवनिर्वाचित महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, महामंत्री श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं श्री कार्यकारी सचिव सुरेश राम।

राजीव अग्रवाल, अमरजीत सिंह, राज कुमार सराफ, राजेश कुमार खेतान, सुनील सराफ, राज कुमार अग्रवाल, राज कुमार, अजय कुमार, किशोर कुमार अग्रवाल मनोज आनंद, सुनील कुमार गुप्ता, दिलजीत खन्ना एवं गणेश कुमार खेमका को जगह मिली है।

प्रस्ताव पारित : आम सभा में उद्योग, ऊर्जा, जीएसटी, नगर विकास, श्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर, आइटी, कम्यूनिकेशन, सूचना का अधिकार और फार्मा से संबंधित कई प्रस्ताव पारित किये गये।

नई राह पर चलकर गढ़ेंगे नए आयाम

पी. के. अग्रवाल ने सभी उद्यमियों और व्यवसायियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए वे सतत् प्रयत्नशील रहेंगे।

दैनिक जागरण से खास बातबीत में उन्होंने कहा कि उनकी तीन प्राथमिकताएं (बड़े उद्योग, लघु उद्योग और जीएसटी) होंगी। कौशल विकास पर भी फोकस होगा। इसी के साथ चैम्बर का दायरा बढ़ाने की कोशिश होगी। सरकार के सहयोग से जीएसटी से जुड़ी अड़चनें दूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि 27 साल बाद केन्द्र और राज्य में एक सोच वाली सरकार बनी है। हम चाहेंगे कि बिहार को इसका भरपूर लाभ मिले। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम इसका ताजा उदाहरण हैं। केन्द्र के सहयोग से इन राज्यों ने विकास कर नई पहचान बनाई। निवेश बढ़ा, रोजगार मिला और इन राज्यों का चहुंमुखी विकास हुआ। बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में किसी तरह की अड़चन है तो हमारी मांग होगी कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए, जिससे सूबे में बड़ा निवेश आ सके। बकौल अग्रवाल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र में बिहार के पास कोई रॉ मैटेरियल नहीं है। अगर हम दूसरे राज्य से कच्चा माल लाकर यहाँ उत्पादन करते हैं तो लागत बढ़ जाती है और हम प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि कच्चा माल लाने में जो किराया लगता है। उस पर हमें सब्सिडी मिले।

(दैनिक जागरण, 27.9.2017)

बाहरी उद्योगपतियों को बिहार लाना बड़ी चुनौती: अग्रवाल

वस्तु एवं सेवाकर यानी जीएसटी हमारे लिए एक चुनौती से कम नहीं था। नयी कर प्रणाली होने के कारण राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी काफी परेशान थे। जीएसटी के बारे में विस्तृत जानकारी देकर उन्हें इसके लिए तैयार करना था। वाणिज्य कर विभाग से मिले सहयोग से यह काम आसान हो पाया, लेकिन बाहरी उद्योगपतियों को लाने में उतने सफल नहीं हुए, जितना उन्होंने उम्मीद की थी।

यह बातें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के नव निर्वाचित अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने प्रभात खबर के साथ विशेष बातचीत में कहीं। उन्होंने कहा कि मेरे सामने कई चुनौतियां हैं, उसे इस कार्यकाल में पूरा करने की हर कोशिश करूंगा, ताकि राज्य में उद्योग का नया माहौल पैदा हो और बेरोजगारों को राज्य में ही रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि पिछले साल दिसम्बर में चैम्बर अध्यक्ष का पद संभालने के बाद मेरे लिए जीएसटी के लिए उद्यमियों और व्यवसायियों को तैयार करना आसान नहीं था। चैम्बर की ओर से न केवल पटना बल्कि वाणिज्य-कर विभाग के साथ उनके सहयोग से राज्य के विभिन्न भागों में स्थित जिला चैम्बर एवं व्यावसायिक संगठनों के प्रांगण में भी जीएसटी के विशेषज्ञों को भेजकर उन्हें जीएसटी की जानकारी दी गयी। उसी का परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में उद्यमी और कारोबारियों ने जीएसटी में अपना निबंधन कराया है।

उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी सेतु पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक के कारण उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के बीच की व्यावसायिक गतिविधियों को सक्रिय बनाने के लिए लगातार यह प्रयास किया गया कि दीघा-पहलेजा एवं आरा-छपरा सड़क पुल को शीघ्र चालू किया जाये, जिसके कारण चैम्बर को यह सफलता मिली। अग्रवाल ने बताया कि रैक साइडिंग की कमी के कारण राज्य के बाहर से माल मंगाने एवं भेजने में हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम राज्य के प्रत्येक प्रमुख जिला में दो-दो रैक साइडिंग का निर्माण किया जाये। इसके लिए भी मैं प्रयत्नशील हूँ। उन्होंने बताया कि पटना में स्थित एयरपोर्ट का विस्तारीकरण एवं नया हवाई अड्डा के निर्माण के लिए भी पिछले साल लगातार प्रयास किया जिसका प्रतिफल है कि पटना के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य के उद्यमियों को पूंजी निवेश की अपनी क्षमता बहुत ही सीमित है, इसलिए पूंजी निवेश के लिए बाहर के पूंजी को आकृष्ट करना है, जो तभी संभव है जब उनको कोई विशेष सुविधा अन्य राज्य की भांति दिया जा सके। विशेष सुविधा के लिए चैम्बर आनेवाले दिनों में केन्द्र सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखेगा ताकि राज्य में निवेश के लिए उद्योगपति आकृष्ट हो और यहाँ बड़े स्तर पर निवेश हो।

बेहतरी के लिए अधिकारियों से की जायेगी बात : चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि राज्य के औद्योगिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से उद्यमियों के समक्ष आ रही प्रमुख समस्या जमीन से संबंधित है, उस पर लगातार सरकार एवं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का ध्यान दिलाया है। उन्होंने बताया कि मेरे सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती राज्य में अवस्थित औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक प्रांगण में प्रचुर मात्र में बेहतर क्वालिटी की बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में पूर्व से स्थापित ऊर्जा इकाइयों के आधुनिकी-करण के साथ-साथ नयी इकाइयों की स्थापना करना है। इसके लिए सरकार पर दवाब बनाना है।

श्री अग्रवाल ने बताया कि राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए बैंकों के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ बैठक एवं पत्राचार किया है, ताकि राज्य में व्यापार एवं उद्योग के लोगों को सहजता से कर्ज मिल सके। लेकिन इसमें बैंकों का रवैया अच्छा नहीं दिख रहा है। इस संबंध में सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है। राज्य के लिए बन रही नयी श्रम नीति के संबंध में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के हित को ध्यान में रखते हुए श्रम संसाधन विभाग को चैम्बर की ओर से सुझाव समर्पित किया गया है। राज्य में बहुत सालों के बाद यह पहला अवसर आया है जब राज्य एवं केन्द्र में एक ही दल की सरकार का गठन हुआ है। औद्योगीकरण एवं आर्थिक विकास केन्द्र सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं है। उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेशों का विकास केवल इसलिए संभव हो सका कि उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा केन्द्र द्वारा दिया गया।

(साभार : प्रभात खबर, 28.9.2017)

GST MEASURES BRING SMILES, CHEER

Traders, entrepreneurs and people from different walks of life welcomed the latest decisions of the Goods and Services Tax (GST) Council chaired by Union finance minister Arun Jaitley to provide relief to them. The GST Council, in its meting held in New Delhi reduced tax rate on 27 different items, increasing the cut-off limit from Rs 75 lakh to Rs 1 crore annual turnover for those eligible for "composition scheme" and giving relief to traders with a turnover of Rs1.5 crore from monthly filing of tax returns to quarterly filing.

Bihar Chamber of Commerce and Industries (BCCI) President P. K. Agrawal told The Telegraph that the steps announced by the GST Council will simplify lives of traders and entrepreneurs.

"Increasing the cut-off limit to Rs 1 crore per annum for being eligible for composition scheme will now cover more persons, traders and entrepreneurs, under it. They will not face hassles for filing three tax returns every month and will have to file summarised tax returns every three months and will have to pay tax as a fixed percentage applicable to their nature of business,"he said.

The BCCI President added that the decision of the GST Council to form a panel to look into the problems being faced by the people in the wake of GST and address them suitably was a good move that would make the new "one nation, one tax regime" simpler and easier.

"We have given more suggestions to the central and the state governments on the basis of difficulties and problems being faced by our members. We will now wait for more relief after the latest moves announced by the Centre. We want steps that do not reduce the revenues of the government, but at the same time provide relief to the people," Agrawal added.

(Source - The Telegraph, 8.10.2017)

सभी के लिए खुला है मेघालय का दरवाजा

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज में महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद का अभिनंदन समारोह

महामहिम राज्यपाल, मेघालय माननीय श्री गंगा प्रसाद को चैम्बर का मेमेन्टो प्रदान कर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। चैम्बर अध्यक्ष की दाँयी ओर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी तथा महामहिम राज्यपाल की बाँयी ओर माननीय महापौर श्रीमती सीता साहू, माननीय विधायक श्री संजीव चौरसिया एवं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या श्रीमती सुषमा साहू।

मेघालय का दरवाजा हर किसी के लिए खुला हुआ है। सभी का वहाँ स्वागत है। ये बातें मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने दिनांक 21 अक्टूबर 2017 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आयोजित अभिनंदन समारोह में कहीं। मौके पर चैम्बर के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल, मेयर सीता साहू, दीघा के विधायक संजीव चौरसिया, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या सुषमा साहू, चैम्बर उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर एवं मुकेश जैन के अलावा बड़ी संख्या में चैम्बर के सदस्य मौजूद थे। आयोजन में गंगा प्रसाद को शॉल व मोमेंटो देकर अध्यक्ष ने सम्मानित किया।

दोनों राज्यों के संबंध में आयेगी प्रगाढ़ता : गंगा प्रसाद ने कहा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेरा करीब 30 साल का पुराना संबंध है जो आगे भी बना रहेगा। राज्यपाल का पद तो एक सम्मान है, लेकिन मैं जिस तरह से पहले था, वैसा ही आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। राज्यपाल बनने के बाद बहुत कम समय ही मेघालय में रह पाया हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी पटना आऊं, आप सब से मुलाकात करूँ आप सब से जो स्नेह-प्यार है, वह हमेशा बना रहेगा। सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश हर वक्त समाज की भलाई के उद्देश्य से ऐसे कार्यों को करते रहने की होती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि उनका ध्यान बिहार पर रहता है। राज्यपाल बना कर उन्होंने सम्मनित किया है। अपने संबोधन में उन्होंने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यादों को भी साझा किया।

दोनों राज्यों में हो एक्सचेंज प्रोग्राम : अपने संबोधन में चैम्बर अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने कहा कि गंगा प्रसाद मेघालय में हमारे प्रतिनिधि हैं। हमारी पहल ऐसी हो कि दोनों राज्यों के बीच प्यार व आपसी संबंध और मजबूत बने। गंगा प्रसाद जी करीब 30 सालों तक हमारे रिप्रेजेंटिटेटिव रहे हैं। मेयर सीता साहू ने कहा कि गंगा प्रसाद का मेघालय का राज्यपाल बनना बड़ी बात है। वहीं सुषमा साहू ने अपनी बात रखते हुए कहा कि गंगा प्रसाद एक निहायत ही सज्जन व्यक्ति हैं। मुझे जब कभी भी जरूरत पड़ी, उनका मार्गदर्शन मिला। आयोजन में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष ओ. पी. साह के अलावा कई अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

(साभार : प्रभात खबर, 22.10.2017)

विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर चैम्बर में नि:शुल्क नेत्र जाँच शिविर

नेत्र जाँच शिविर में नेत्र सर्जन डॉ० शशि मोहनका को चैम्बर का मेमेन्टो देकर सम्मानित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री आशीष शंकर, श्री सुबोध कुमार जैन, श्री सांवल राम डूलिया, डॉ० गीता जैन एवं श्री राजेश जैन।

शिविर में आँखों की जाँच करते डॉ० शशि मोहनका। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, श्री सुबोध जैन, श्री सांवल राम डूलिया एवं श्री आशीष शंकर।

शिविर में नेत्र जाँच कराते व जाँच की प्रतीक्षा करते लोग।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर चैम्बर प्रांगण में एक नि:शुल्क नेत्र जाँच शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने किया। शिविर में आर्थिक रूप से कमजोर 200 लोगों के आंखों की जाँच की गयी एवं आँखों को कैसे सुरक्षित रखा जाये इस सम्बन्ध में सुझाव दिया गया।

मौके पर चैम्बर अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बचने योग्य अंधेपन और दृष्टि नुकसान के वैश्विक मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए जागरूकता का प्रसार करना है।

शिविर में प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक व श्रीबालाजी नेत्रालय के निदेशक डॉ० शशि मोहनका की टीम द्वारा आंखों की जाँच की गयी।

श्री मोहनका ने बताया कि आँखों की जाँच के दौरान विभिन्न प्रकार के मरीज मिले। इसमें किसी का पावर गड़बड़, किसी को चश्में की आवश्यकता, किसी को परदे की बीमारी, किसी को आँखों से पानी निकलना आदि।

चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि मोतियाबिन्द के 15 मरीजों का चुनाव किया गया है उनका नि:शुल्क ऑपरेशन डॉ० शशि मोहनका द्वारा उनके क्लिनिक श्री बालाजी नेत्रालय, नाला रोड, पटना में 22.10.2017 को किया जायेगा।

इस अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, श्री ओ० पी० टिबड़ेवाल उपस्थित थे। श्री सुबोध कुमार जैन, श्री राजेश जैन, श्री सॉवल राम डूलिया, श्री आशीष शंकर एवं डॉ० गीता जैन ने शिविर के सफल संचालन में सक्रिय भूमिका निभाई।

चैम्बर ने 15 लोगों का कराया नि:शुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन

फीता काटकर शिविर का उद्घाटन करते माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा। उनकी दाँयीं ओर माननीय विधायक श्री नीतिन नवीन, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल एवं बाँयीं ओर श्री सावल राम डोलिया। पीछे दाँयें से उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, पूर्व उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से पटना के नाला रोड स्थित श्री बालाजी नेत्रालय में दिनांक 22.10.2017 को नि:शुल्क मोतियाबिन्द ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बिहार के माननीय श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। इस शिविर में माननीय विधायक अरूण कुमार सिन्हा एवं नितिन नवीन भी सम्मिलित हुए। शिविर में कुल 15 रोगियों के मोतियाबिन्द का ऑपरेशन हुआ। डॉ. शशि मोहनका एवं उनके टीम द्वारा श्री बालाजी नेत्रालय में कराये गये इस मोतियाबिंद ऑपरेशन का सारा खर्च बिहार चैम्बर ने वहन किया है। साथ ही रोगियों को दवा एवं चश्मा भी उपलब्ध कराया है। बताते चलें कि 12 अक्टूबर को चैम्बर ने विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर नि:शुल्क जांच की व्यवस्था की थी। शिविर में काफी संख्या में लोगों ने अपनी-अपनी आँखों की जाँच कराई थी। इनमें ज्यादातर लोगों को दवा एवं आँखों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई थी। परंतु उनमें से करीब 15 ऐसे लोग सामने आए थे जिन्हें तत्काल ऑपरेशन की आवश्यकता थी। इन 15 लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बिहार चैम्बर ने उनकी आँखों का ऑपरेशन कराने का निर्णय लिया था।

इस मौके पर बिहार चैम्बर के उपाध्यक्ष एन के ठाकुर एवं मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, महामंत्री अमित मुखर्जी समेत वरीय सदस्यों में पी के सिंह, गणेश कुमार खेतड़ीवाल, ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, पशुपति नाथ पाण्डेय, सुबोध कुमार जैन, सावल राम डोलिया, किशोर कुमार अग्रवाल, राजेश जैन के साथ-साथ आधार महिला के सहयोगी एम पी जैन उपस्थित थे। चैम्बर अध्यक्ष पी के अग्रवाल ने कहा कि चैम्बर अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सदैव आगे रहा है और रहेगा। (साभार : दैनिक भास्कर, 23.10.2017)

माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल। साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

शिविर में ऑपरेशन किये गये मरीजों के साथ पीछे कुर्सी पर बैठे (दाँयें से) क्रमश: माननीय विधायक श्री अरूण कुमार सिन्हा, माननीय श्रम संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय विधायक श्री नीतिन नवीन एवं डॉ० शशि मोहनका। पीछे चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, राजेश जैन, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, सावल राम डोलिया, श्री सुबोध कुमार जैन, पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं अन्य।

चैम्बर में नई फायर पॉलिसी एवं फायर सेफ्टी पर कार्यशाला आयोजित

आग से बचाव को लाएं जागरूकता – श्री पी. एन. राय

कार्यशाला को सम्बोधित करते महानिदेशक-सह-समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएं श्री पी० एन० राय, भा०पु०से०। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी तथा बाँयीं ओर निवर्त्तमान महामंत्री श्री शशि मोहन।

आग को लेकर आमलोग काफी उदासीन हैं। इसी के कारण आये दिन आग लगने की घटना होती रहती है। अगर आम लोग इसके प्रति जागरूक हो जाये तो घटना में काफी कमी लायी जा सकती है। ये बातें महानिदेशक सह महासमादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएं पी. एन. राय ने कहीं।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से दिनांक 30.10.2017 को नई फायर पालिसी एवं फायर सेफ्टी विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए पी. एन. राय ने कहा कि लोग केवल विभाग को दोषी ठहराते हैं और उनकी कमियों को गिनाते हैं।

उन्होंने कहा कि दुकानदार अपनी दुकान की सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में हर रास्ते को बाधित कर देते हैं जिसके कारण आग लगने पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है।

इसके पूर्व बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने सूबे में अग्निशामन विभाग के कार्यकलाप पर प्रकाश डालते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर महानिदेशक का ध्यान दिलाया। चैम्बर के उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर ने महानिदेशक पी. एन. राय को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर चैम्बर के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन, महासचिव अमित मुखर्जी, पूर्व अध्यक्ष ओ. पी. साह एवं मोती लाल खेतान, पूर्व महासचिव शशि मोहन आदि कई सदस्य मौजूद थे।

(साभार : प्रभात खबर, 31.10.2017)

जीएसटी: कई जरूरी वस्तुएं सस्ती होंगी

केन्द्र सरकार रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले शैंपू, पाउडर समेत कई वस्तुओं पर जल्द जीएसटी की दरें घटाएगी। जीएसटी परिषद उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो आम जनता से जुड़ी हुई हैं और उन पर एकीकृत टैक्स की उच्च दर लागू है। जीएसटी परिषद नौ नवंबर को होने वाली बैठक में सफेद चौकलेट, मस्टर्ड सॉस, कस्टर्ड पाउडर, शैम्पू और बालों में लगाने वाली क्रीम पर दरों को 12 से 18 प्रतिशत के बीच तय कर सकती है। इन वस्तुओं पर 28 फीसदी जीएसटी लागू है। इसी तरह से स्टेशनरी से जुड़ी ज्यादातर सामग्री की दरें घटाई जाएंगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक परिषद सौ से ज्यादा उन चीजों पर दरें घटाएगी, जिनका उपयोग रोजमर्रा के कामकाज में होता है। इनमें से अधिकतर वस्तुओं पर कर की दर 28 फीसदी रखा गया था।

स्टेशनरी उत्पादों में फाइलें, किताबों की बाइंडिंग से जुड़ी सामग्री, लेटर क्लिप्स, लेटर कॉर्नर्स, पेपर क्लिप्स, इंडेक्सिंग टैग और कार्यालयों में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं पर 18 फीसदी की दर लागू की गई थी।

सरकार इसकी समीक्षा कर रही है कि रोजमर्रा की कौन सी वस्तु पर सही दर लागू है और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके दरों में कमी लाने की जरूरत है। मालूम हो कि परिषद की 22वीं बैठक में 22 वस्तुओं तथा 5 सेवाओं के टैक्सों में कटौती की गई थी।

दरों में समानता नहीं : रोजाना इस्तेमाल में लाई जाने वाली कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में समानता नहीं है। यही वजह है कि ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार की गई थी, जिस पर पिछली बैठक में भी चर्चा हुई थी। सरकार तीन माह से लगातार इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षकारों से सुझाव ले रही है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 13.10.2017)

पेट्रोलियम उत्पाद भी आएं जीएसटी के तहत : उप मुख्यमंत्री

बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने की वकालत की। मोदी जीएसटी नेटवर्क के तकनीकी मुद्दों को देख रहे मंत्रियों के समूह (जीओएम) के प्रमुख भी हैं। इसके अलावा मोदी जीएसटी परिषद के सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों का मानना है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाया जाना चाहिए। वहीं कुछ अन्य राज्य ऐसा नहीं चाहते।

उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि आगामी दिनों में यह मुद्दा हल हो जायेगा। मुझे लगता है कि जल्द पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी का हिस्सा होंगे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह उनकी निजी राय है। दुनिया भर में पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे में ही आते हैं।

श्री मोदी ने पिछले महीने मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। यह बैठक जीएसटी नेटवर्क से जुडे मुद्दों को हल करने की रूपरेखा तय करने के लिए थी। उन्होंने कहा कि मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि आगामी दिनों में अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, जो शुरुआती दिक्कतें आयी हैं वे हल हो जायेंगी।

उन्होंने स्वीकार किया कि जीएसटी क्रियान्वयन के शुरुआती दिनों में कुछ समस्याएँ रही हैं, लेकिन आगमी दिनों में अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत स्थिति में होगी।

(साभार : प्रभात खबर, 13.10.2017)

इनकम टैक्स वकीलों व सीए का प्रदर्शन

टैक्स और पेनाल्टी की लेकर इनकम टैक्स वकील और सीए ने पटना सिटी वाणिज्यकर कार्यालय में प्रदर्शन किया।

इससे पहले सीए ने वाणिज्य कर उपायुक्त दिवाकर प्रसाद से मिलकर समस्या रखी। लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सीए का कहना था कि जीएसटी में थ्रीबी टैक्स का कहीं प्रावधान नहीं है, जबकि अगस्त व सितम्बर के टैक्स में इसे जोड़ा गया है। साथ ही पेनाल्टी भी अधिक लगायी जा रही है। इतनी रकम व्यवसायी भरने को तैयार नहीं हैं। उपायुक्त का कहना है कि समस्या से वरीय अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 19.10.2017)**

अगस्त में 3394 करोड़ रुपये घटकर 90669 करोड़ रुपया हुआ जीएसटी संग्रह

देश में जीएसटी लागू होने के दूसरे महीने अगस्त में कुल 90, 669 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ। एक आधिकारिक वक्तव्य में यह जानकारी दी गयी है। बयान में कहा गया, विभिन्न श्रेणियों में जीएसटी के तहत 25 सितम्बर तक संग्रह हुआ है। इसमें कंपोजिशन स्कीम का चयन करने वाले 10.24 लाख करदाताओं द्वारा दिया गया जीएसटी का आंकड़ा शामिल नहीं हैं। देश में अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र की जीएसटी व्यवस्था को एक जुलाई से लागू किया गया। इसमें एक दर्जन से अधिक केन्द्रीय और राज्य स्तर के अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है। जीएसटी लागू होने के पहले माह जुलाई के लिये 31 अगस्त तक कुल 94,063 करोड़ रुपये का कर प्राप्त हुआ। अगस्त महीने के लिए जीएसटी भुगतान और जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 सितम्बर थी।

रुपया 94,063 करोड़ जुलाई में था राजस्व : • **68.20** लाख लोगों को अगस्त के लिए करना था कर का भुगतान • **37.63** लाख लोगों ने 25 सितम्बर तक दाखिल किया जीएसटीआर-3बी • **10.24** लाख कंपोजिशन स्कीम का चयन करने वाले करदाताओं का जीएसटी आंकड़े में शामिल नहीं

25 सितम्बर तक विभिन्न श्रेणियों में जीएसटी संग्रह : • **14,402** करोड़ केन्द्रीय जीएसटी से • **21,067** करोड़ राज्य जीएसटी से • **47,377** करोड़ रुपये एकीकृत जीएसटी से • 7,823 करोड़ लग्जरी उत्पादों पर लगे क्षतिपूर्ति उपकर से। **(साभार : प्रभात खबर, 27.9.2017)**

जीएसटी रिटर्न न भरने वालों की बनेगी राज्यवार सूची

जानबूझकर जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं वाले कारोबारियों को अब टैक्स अधिकारियों के सवालों का सामना करना पड़ेगा। सरकार जीएसटी रिटर्न दाखिल न करने वाले कई लाख व्यापारियों की राज्यवार सूची तैयार कर रही है। नॉन फाइलर्स व्यापारियों की सूची सभी राज्यों को भेजी जाएगी। इसके बाद केन्द्र और राज्यों के अधिकारी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 11.10.2017)

जीएसटी नियमों में बदलाव का आम लोगों पर असर

रेस्तरां में 1000 रु. के बिल पर 60 रु. बचेंगे, पर आयुष दवाओं पर कम टैक्स का लाभ नहीं

इन बदलावों के लिए सरकार जल्द जारी करेगी नोटिफिकेशन

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के नियमों में बदलाव से आम लोगों के लिए रेस्तरां में खाना सस्ता होगा। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल ने सामान्य श्रेणी के एसी रेस्तरां पर टैक्स घटाने का मन बना लिया है। अभी यहाँ फूड बिल पर 18% टैक्स लगता है। इसे 12% किया जाएगा। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार कंपोजीशन स्कीम की लिमिट बढ़ने का असर भी रेस्तरां बिल में कुछ कटौती के रूप में दिख सकता है। इसके अलावा घरों में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें भी सस्ती हो सकती हैं। दूसरे राज्यों के सर्विस प्रोवाइडर्स और अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के माल की ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को रजिस्ट्रेशन से राहत से भी आम लोगों को फायदा होगा।

जीएसटी काउंसिल ने 6 अक्टूबर की बैठक में कंपोजीशन स्कीम के लिए सालाना टर्नओवर की सीमा 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए करने का फैसला किया। इस स्कीम में ट्रेडर को पूरे टर्नओवर पर 1%, मैन्युफैक्चरर को 2% और रेस्तरां को 5% टैक्स देने का प्रावधान है। ये सभी फैसले नोटिफिकेशन आने के बाद ही लागू होंगे।

घरेलू इस्तेमाल वाली कई चीजों के घट सकते हैं दाम

एसी रेस्तरां: बिल पर टैक्स 18% से घटकर 12% होगा : नॉन-एसी रेस्तरां में खाने के बिल पर अभी 12% और एसी रेस्तरां में 18% टैक्स लगता है। एसी रेस्तरां में टैक्स रेट घटाकर 12% करने का नोटिफिकेशन जल्दी आ सकता है। इसका सीधा असर ग्राहक के बिल पर होगा। अभी 1,000 रुपए के फूड बिल पर 180 रुपए टैक्स लगता है। यह 120 रुपए हो जाएगा। जीएसटी से पहले बिल पर 6% सर्विस टैक्स और लगभग इतना ही वैट लगता था। यानी टैक्स पुराने स्तर पर आ जाएगा।

कंपोजीशन वाले रेस्तरां में भी कम हो सकता है ग्राहक के खाने का बिल : अभी तक सालाना 75 लाख रुपये टर्नओवर वाले रेस्तरां, पर 5% टैक्स लगता था। कंपोजीशन स्कीम की लिमिट बढ़ने से एक करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले रेस्तरां भी इस दायरे में आ जाएंगे। यानी जिन रेस्तरां का टर्नओवर 75 लाख से एक करोड़ रुपए तक है, वे भी कंपोजीशन का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे रेस्तरां में जाने वाले ग्राहकों को कम टैक्स का लाभ मिलेगा।

छोटे मैन्युफैक्चरर की लागत कम होगी, खरीदार को मिल सकता है फायदा : घरों में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर छोटे-मोटे आइटम छोटे कारोबारी ही बनाते हैं। कंपोजीशन की लिमिट बढ़ने और तिमाही रिटर्न के लिए टर्नओवर की सीमा 1.5 करोड़ रुपए करने से कंप्लायंस कॉस्ट कम होगी। मैन्युफैक्चरर कम लागत का फायदा ग्राहकों को दे सकते हैं। कंपोजीशन वाले मैन्युफैक्चरर पर अभी 2% टैक्स का प्रावधान है। जीएसटी काउंसिल इसका इनपुट क्रेडिट भी देने पर विचार कर रही है।

दूसरे राज्यों के सर्विस प्रोवाइडर्स को राहत : फ्रीलांसर और ऐसे दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स को भी राहत दी गई है। पहले नियम था कि दूसरे राज्यों में सर्विस देने वालों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले ही वे साल में 20 लाख रुपए से कम की सर्विस देते हों। इसमें संशोधन करते हुए साल में 20 लाख रु. तक की सर्विस देने वालों को रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है। यानी उनके लिए कोई कंप्लायंस नहीं रह जाएगा। **(साभार : दैनिक भास्कर, 11.10.2017)**

एसबीआई लघु व्यापारियों को रियायती दर पर कर्ज देगा

देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) नोटबंदी और जीएसटी के प्रभावों से जूझ रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए आगे आया है।

उसने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग (एसएमई) के कारोबारियों को रियायती दर पर कम अवधि का कर्ज देने का एलान किया। इस योजना को एसएमई असिस्ट नाम दिया गया है, इसके तहत एमएसएमई ग्राहकों को जीएसटी के तहत फंसे इनपुट क्रेडिट दावों के आधार पर ऋण दिया जाएगा।

बैंक के मुख्य महाप्रबंधक (एसएमई) वी रामलिंगम ने कहा कि छोटे उद्योगों को इनपुट क्रेडिट प्राप्त होने तक उनकी कार्यशील पूंजी की कमी को दूर करेगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 13.10.2017)**

आयुध निर्माणी नालंदा में चालू होंगी दो और यूनिटें

आयुध निर्माणी नालंदा बीएमसीएस के उत्पादन में देश का पहला कारखाना बना

केन्द्रीय रक्षा राज्यमंत्री डॉ सुभाष भामरे ने आयुध निर्माणी नालंदा, राजगीर में बने बायो मॉड्यूल चार्ज सिस्टम (बीएमसीएस) का एकलाखवां मॉड्यूल देश को सौंपा। बीएमसीएस का इस्तेमाल बोफोर्स तोप में किया जाता है। केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि मौजूदा समय में फैक्टरी की तीन यूनिटें काम कर रही हैं। जल्द ही दो और यूनिटें चालू की जायेंगी। आयुध निर्माणी के सभा भवन में आयोजित समारोह में डॉ भामरे ने कहा कि बीएमसीएस का उत्पादन करने वाला यह भारत का अकेला कारखाना है।

उन्होंने कहा कि जब से केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, इस फैक्टरी के विकास पर काम हो रहा है। केन्द्र सरकार के पास इसके लिए पैसे की कमी नहीं है। सरकार इस फैक्टरी के बारे में पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि आज गौरव का दिन है कि यहाँ से एकलाखवां बीएमसीएस मॉड्यूल

उत्पादित हो चुका है। आयुध निर्माणी के महाप्रबंधक शरद घोड़के ने कहा कि पहले बीएमसीएस को विदेश से मंगाना पड़ता था। इससे एक मॉड्यूल के बदले 19 हजार रुपये की लागत आती थी, लेकिन नालंदा में इसे बनाने पर 14 हजार रुपये का खर्च आता है। इससे एक साल में सौ करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में दो लाख बीएमसीएस बनाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन छह महीने के पहले ही एक लाख मॉड्यूल बना लिया गया। यहाँ से बने बीएमसीएस सेना के अर्टिलरी यूनिट के लिए बहुत जरूरी है। **(साभार : प्रभात खबर, 28.9.2017)**

लोन नहीं देने वाले बैंकों पर उद्योग विभाग करेगा कार्रवाई

प्रधान सचिव ने की पीएमईजीपी की समीक्षा

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) में लापरवाही बरतने वाले बैंकों की विरुद्ध कार्रवाई के लिए बैंक के चेयरमैन को लिखेगी। खादी ग्रामोद्योग आयोग और उद्योग विभाग से आवेदन को अनुमति मिलने के बाद भी बैंक राज्य के बेरोजगारों को ऋण नहीं दे रहे हैं। यह गंभीर मामला है। वह राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोजगारों को पीएमईजीपी योजना के तहत बैंकों द्वारा ऋण नहीं देने के मामले की समीक्षा कर रहे थे।

पीएमईजीपी की वर्ष 2016-17की स्थिति

श्रेणी	आवेदन मिले	ऋण दिया
सामान्य	2586	558
ओबीसी	5564	1260
अल्पसंख्यक	598	153
एससी	1944	102
एसटी	240	9

उन्होंने कहा कि ऋण के बदले कमीशन मांगे जाने के मामले भी सामने आ रहे हैं। सरकार इसकी जाँच करवा रही है। दोषी पाए जाने वाले बैंककर्मियों पर एफआईआर दर्ज करवाया जाएगा। कहा-उद्योग विभाग ने अपने खर्चे पर राज्य के एसटी-एससी समुदाय के कुछ बेरोजगार युवकों को पटना बुलाया और उनकी परेशानी सुनी। **(साभार : दैनिक भास्कर, 13.10.2017)**

नये उद्यमियों को बियाडा ने दिया दीवाली का तोहफा

व्यापार को आसान बनाने और राज्य के रैंकिंग में सुधार के लिए बियाडा ने पहली बार भूमि आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा है। इसके तहत कुल 71 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन आवेदनों को 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा में कार्यरूप देने के लिए पीसीसी की एक बैठक हुई। इसमें स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण, प्लास्टिक और टेक्सटाइल क्षेत्र की कुल 18 इकाइयों को 4.96 एकड़ जमीन के आवंटन पर सहमति बनी। इससे राज्य में कुल 9949,479 लाख रुपये का निवेश होगा। साथ ही प्रत्यक्ष रूप से 607 लोगों को रोजगार मिलेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 19.10.2017)

शुल्क वापसी दरों को जारी रखने के पक्ष में फियो

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गिनाइजेशन (फियो), दक्षिण क्षेत्र ने केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) से शुल्क वापसी की दर और राज्य शुल्कों में छूट को बरकरार रखने की अपील की है। संगठन का कहना है कि यह बड़े पैमाने पर उद्योगों को प्रभावित करता है। **(हिन्दुस्तान, 28.9.2017)**

राइस मिल में ड्रायर लगाने पर 50% अनुदान

अच्छी पहल : सहकारिता विभाग का प्रस्ताव, ड्रायर मशीन के लिए मिलेगा 6 लाख रुपए अनुदान

पैक्स को मिल के साथ ड्रायर लगाने के लिए सरकार करीब 35 लाख रुपए अनुदान देगी। सहकारिता विभाग ने बिजली चालित चावल मिल स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत प्रतिघंटा दो एमटी (20 क्विंटल) धान की कुटाई की क्षमता वाली चावल मिल की स्थापना के लिए लागत मूल्य 58 लाख रुपए आकलन किया गया है। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। 2017-18 में 260 पैक्स को दो एमटी चावल मिल के साथ ड्रायर मशीन लगवाने का लक्ष्य रखा गया है।

एक ड्रायर मशीन की कीमत 12 लाख रुपए हैं। इसमें सरकार 6 लाख रुपए अनुदान देगी। शेष राशि पैक्स को खुद लगाना है। धान में अधिक नमी को कम करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। 17 प्रतिशत से अधिक नमी वाले धान को ड्रायर मशीन से नमी कम किया जाएगा, ताकि किसानों से दिसम्बर और शुरू जनवरी में जब धान में नमी अधिक रहती है, तब भी धान की खरीद पैक्स में हो सके। नमी के कारण ही अक्सर राज्य में धान की खरीद जनवरी के बाद फरवरी और मार्च में अधिक होती है। अनुदान के अतिरिक्त पैक्स को सहकारिता विभाग कॉरपस फंड के माध्यम से अनुदान के आतिरिक्त उपलब्ध कराएगी। अनुदान के अतिरिक्त 50 प्रतिशत की शेष राशि बाद में पैक्स से विभाग वापस ले लेगा। इससे पैक्स न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद में काफी सुविधा होगी। विकेन्द्रीकृत व्यवस्था में पैक्स और व्यापारमंडल को किसानों से धान खरीद की जिम्मेदारी दी गई है। पैक्स और व्यापारमंडल से एसएफसी धान की जगह चावल लेता है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 13.10.2017)**

अगले साल चालू होगा बरौनी उर्वरक कारखाना

• बरौनी में नए कारखाने की स्थापना एचएफसीएल की पुरानी फैक्टरी के 480 एकड़ के परिसर में ही की जाएगी • सूत्रों के अनुसार अगले साल के अंत तक उत्पादन हो जाएगा शुरू

जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइपलाइन ने बिहार में उर्वरक कारखाने का भी रास्ता साफ कर दिया है। इस कारखाने की स्थापना बरौनी में की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस कारखाने से अगले साल के अंत तक उत्पादन शुरू हो जाएगा।

केन्द्र सरकार ने पिछले साल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और पश्चिम बंगाल स्थित सिंदरी उर्वरक कारखानों के साथ-साथ इस कारखाने से फिर से उत्पादन शुरू करने का फैसला लिया था। इसके लिए केन्द्र सरकार ने एनटीपीसी, कोल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एक विशेष कंपनी बनाई थी।

अकेले बरौनी उर्वरक कारखाने पर केन्द्र सरकार ने करीब 6,000 करोड़ रुपये के निवेश का फैसला लिया है। साथ ही, इस कारखाने को ईंधन की आपूर्ति गेल के जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइपलाइन से ही की जाएगी। इसके लिए गया से खास तौर पर एक सहयोगी पाइपलाइन बेगूसराय जिले तक जाएगी। इस कारखाने का निर्माण बरौनी स्थित हिंन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की पुरानी फैक्टरी के 480 एकड़ के कैंपस में ही किया जाएगा, जो 1999 से बंद पड़ी हुई है। राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक पुरानी फैक्टरी को तोड़ने का काम चल रहा है, जबकि नए कारखाने का निर्माण का काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा।

इस कारखाने के बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पेट्रोलियम मंत्री धमेन्द्र प्रधान के बीच बातचीत भी हुई थी। इस बारे में केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को जल्दी ही निर्माण कार्य शुरू होने का आश्वासन दिया है।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 11.10.2017)

बिहटा-दानापुर फ्लाइओवर पर बनेगा देश का सबसे लंबा साइकिल ट्रैक

साइकिल होगी पटना की पहचान : पटना को जल्द ही एक और नई पहचान मिलने वाली है। यहाँ देश का सबसे लंबे साइकिल ट्रैक बनाने का प्लान तैयार हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है और बहुत जल्द इस पर मोहर लग जाएगी। दो हजार करोड़ की लागत से बिहटा से दानापुर के बीच बनने वाले फ्लाइओवर को पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाने का प्लान है। ग्रिपर बेस पर बनने वाले टू साइडर साइकिल ट्रैक को ग्रीनरी से कवर करने के लिए भी पहले से खाका तैयार किया जाएगा। इस ट्रैक को ऐसे डेवलप किया जाएगा कि प्रदूषण भी कम हो। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों की मानें तो ट्रैक को ऐसा बनाया जाएगा कि लोग बाइक छोड़ साइकलिंग पर जोर देंगे। 21 किलोमीटर लंबे इस साइकिल ट्रैक में कई खास बातें होगी।

ऐसा होगा फ्लाइओवर का लुक : • 21किलो मीटर लंबे फ्लाइओवर पर होगा देश का इकलौता साइकिल ट्रैक • फ्लाइओवर की चौड़ाई सामान्य फ्लाइ-ओवर से काफी अधिक होगी • फ्लाइओवर के दोनों साइड में साइकिल के लिए ग्रिपर ट्रैक बनाया जाएगा • हाईटेक लाइटिंग से फ्लाइओवर को पूरी तरह से

विदेशी लुक दिया जाएगा। साइकिल ट्रैक के डिवाइडर को काफी हाईटेक और आकर्षक बनाया जाएगा • डिवाइडर पर ऐसे पेड़-पौधे लगाए जाएंगे जो वातावरण को पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाएगा। जो पटनाइट्स के लिए लाभदायक हो सकता है • बीच से टू लेन में चलने वाले वाहनों का धुआं कम करने के लिए साइकिल ट्रैक को ग्रीनरी से कवर किया जाएगा।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, (आइनेक्स्ट) 11.10.2017)

बिजली नुकसान को कम करने में बिहार पीछे

बिहार में 41 फीसदी बिजली का नुकसान हो रहा है, जो देश में अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बिजली नुकसान वाला राज्य है। इसका खुलासा केन्द्र सरकार के पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की रिपोर्ट से हुआ है। हर तीन महीने पर जारी होने वाली इस रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 53.7 फीसदी बिजली का नुकसान होता है।

बिहार में बिजली के नुकसान का मुख्य कारण सभी उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं देना है और जिन्हें बिल दी भी जाती है उनसे उसकी वसूली नहीं हो पाना है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 90 लाख उपभोक्ताओं में से 40 लाख उपभोक्ताओं से बिजली बिल की वसूली नहीं हो पाती है। बिहार में 32.5 फीसदी उपभोक्ता को अब भी बिजली बिल नहीं मिल पाता है।

बिजली नुकसान होने के मुख्य कारण : बिजली की चोरी, बिजली बिल का भुगतान नहीं होना, बिजली के तार में पावर जाना, ज्वाइंट तार में बिजली की ज्यादा खपत, उपभोक्ता का कनेक्शन दो केवीए का और उपयोग करते हैं पाँच केवीए।

अधिक बिजली का नुकसान करने वाले राज्य : • अरुणाचल प्रदेश - **53.7%** • बिहार - **41%** • मणिपुर - **36.9%** • मेघालय - **35%** • ओड़िशा - **35%** • उत्तर प्रदेश - **33.6%**

कम बिजली नुकसान वाले राज्य : • आंध्र प्रदेश - **10.9%** • हिमाचल प्रदेश - **11.3%** • गुजरात - **12.4%** • पंजाब - **13%** • कर्नाटक - **15.2%** • तेलंगाना व गोवा - **15.8%**

सूबे में बिजली की स्थिति : • 5000 मेगावाट आवश्यकता • 3700 -3800 मेगावाट हर दिन मिल रहा • 2200-2500 मेगावाट केन्द्र से मिलता है • 1200-1500 मेगावाट बाजार से खरीदारी **(साभार : प्रभात खबर, 13.10.2017)**

आप नहीं देते हैं टैक्स तो कटेगा बिजली व पानी का कनेक्शन

सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिये गये कई फैसले

अगर आप नगर निगम को होल्डिंग टैक्स नहीं देते हैं, तो निगम आपके घर की बिजली, पानी कनेक्शन को काटने की कार्रवाई करेगा। इसके बाद भी अगर आप जुर्माना सहित टैक्स नहीं देते हैं, तो संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की जायेगी। इसके लिए नगर निगम के चारों अंचलों में राजस्व पदाधिकारी के निर्देशन में 10 सदस्यीय टीम का गठन किया जायेगा। मौर्यालोक कॉम्प्लैक्स स्थित निगम मुख्यालय में सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। टीम का गठन स्थायी रूप से किया जायेगा। किसी भी बड़े बकायेदार को नगर निगम नोटिस देगा फिर 21 दिन के बाद कार्रवाई शुरू की जायेगी।

अतिकमण हटाने के लिए भी बनी विशेष टीम : अब सभी अंचलों में विभिन्न जगहों से अतिक्रमण हटाने के लिए भी टीम स्थानीय तौर पर रहेगी। जिसको टास्क फोर्स के नाम से जाना जायेगा। टास्क फोर्स के पास ड्रेस, टोपी, जूते से लेकर अतिक्रमण हटाने के जरूरी संसाधन मसलन जेसीबी व ट्रैक्टर स्थायी तौर पर रहेंगे। चार अंचलों में से कंकड़बाग, बांकीपुर व पटना सिटी अंचल में एक-एक टीम रहेगी। जबकि नूतन राजधानी अंचल में दो टीमें रहेंगी।

(साभार : प्रभात खबर, 19.10.2017)

रेल टिकट पर होगा नाश्ते और खाने का विवरण

ट्रेनों से सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का विवरण और उसके मूल्य की जानकारी अब यात्रियों को पहले हो मिल जाएगी। ऐसा होने पर वेंडर मनमानी कीमत नहीं वसूल सकेगा क्योंकि अब आरक्षित टिकट के पीछे खानपान का विवरण तो दर्ज होगा ही साथ ही ई-टिकट कराने वालों को भी ऑनलाइन विवरण दिखेगा। ट्रेन में खानपान सेवा देने वाली कंपनी पर रेलवे का कोई जोर नहीं होता। अधिक पैसा लेने पर यात्री शिकायत कर थक जाते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। सबसे ज्यादा शिकायत खराब गुणवत्ता की होती है।

कैग की रिपोर्ट में हुई फजीहत के बाद रेलवे ने अपनी छवि सुधारने के लिए यात्रा टिकट को माध्यम बनाया है। ट्रेनों में अलग-अलग खानपान व्यवस्था के तहत ब्योरा जुटाया जा रहा है। रेलवे के वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आरक्षण केन्द्र से लेकर ई-टिकट सेवा में यह सुविधा होगी। ई-टिकट पर वस्तुओं व कीमतों की सूची मोबाइल पर दिखेगी। **(दैनिक जागरण, 28.9.2017)**

मधेपुरा रेल कारखाने में 11 अक्टूबर से काम होगा शुरू

जिले के लोगों के लिए दिन एक बड़े सपने का सच होने जैसा होगा। बहुप्रतीक्षित रेल विद्युत इंजन कारखाने में इंजन निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इस विशेष मौके पर रेलवे बोर्ड के अधिकारी, अलस्टॉम कंपनी के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे। शहर से करीब चार किलोमीटर दूर चकला चौक के नजदीक रेल विद्युत इंजन कारखाना बनकर लगभग तैयार हो चुका है।

कारखाना में विद्युत इंजन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कारखाने के अंदर इसको लेकर तैयारी जोर-शोर से चल रही है। बड़ी बात यह कि इस फैक्ट्री की स्थापना के लिए 26 जनवरी 2016 को ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने कान्ट्रैक्ट साइन किया था। 4 अक्टूबर 1016 को फैक्ट्री निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। रेल विद्युत इंजन निर्माण में अग्रणी फ्रांस की अलस्टॉम कंपनी को रेल विद्युत इंजन निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

एक हजार इंजन खरीदने का ऑर्डर : प्रोजेक्ट के साथ गहराई से जुड़े रहे डीएम मो. सोहैल ने बताया कि भारत सरकार 1000 इंजन खरीदने का ऑर्डर दे चुकी है। डीएम ने बताया कि रेल फैक्ट्री में निर्माण कार्य शुरू होना मधेपुरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण कोसी-सीमांचल और प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.10.2017)

रेलवे की प्राथमिकता सुरक्षा व समय का पालन : डीआरएम

दानापुर के नए डीआरएम रंजन प्रकाश ठाकुर ने अपने पहले संवाददाता सम्मलेन में कहा कि यात्री सुविधाओं के साथ समय पर और सुरक्षित मंजिल पर पहुंचने की कामना लेकर रेल में सफर करते हैं।

उन्होंने कहा कि रेल की प्राथमिकता भी यही होती है कि यात्री मुस्कान के साथ यात्रा करें। इसके लिए संरक्षा, सुरक्षा, समयपालन और यात्री सुविधा रेल की पहली प्राथमिकता होती है। पिछले कुछ महीनों में लगातार हुई दुर्घटनाओं को लेकर संरक्षा पर उठे सवालों के जवाब में डीआरएम ने कहा कि इस मंडल में आते ही संरक्षा के मामले को लेकर समीक्षा बैठक और कुछ जगहों का निरीक्षण उन्होंने किया है। इस आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ यात्रियों को भरोसा दिलाता हूँ कि इस मंडल में निश्चिंत होकर यात्रा करें। मंडल के मुख्य रेलमार्ग झाझा-मुगलसराय के बीच गाड़ियों की रफ्तार 110 से बढ़ा कर 130 किलोमीटर करने पर तेजी से काम हो रहा है। अगले तीन महीने में मंडल के चार महत्वपूर्ण स्टेशनों – पटना, दानापुर, राजेन्द्रनगर और पाटलिपुत्र स्टेशन पर आवागमन के लिए ओला गाड़ियों की सुविधा मिलने लगेगी। पटना-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में 21 की जगह 22 कोच होंगे। राजधानी एक्सप्रेस से जेनेटर कार हटा दिया गया है। इससे साल में सात करोड़ का फायदा रेल को होगा। वहीं ध्वनि और धुआं प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। दानापुर स्टेशन पर आरआरआई का काम दिसम्बर तक पूरा हो जाएगा। दानापुर में रेलवे सिनेमा के सामने निर्माणाधीन अतिरिक्त प्लेटफॉर्म का काम मार्च में पूरा हो जाएगा। इसके बाद उतरी बिहार की गड़ियों का परिचालन भाया पाटलिपुत्र और दानापुर होने लगेगा। दानापुर स्टेशन का दूसरा साउथ प्रेवश द्वार मार्च से शुरू हो जाएगा। यहाँ दो करोड़ की लागत से दो तल्ला टिकट आरक्षण घर, सर्कुलेटिंग एरिया, खान-पान आदि की सुविधा मिलने लगेगी। इस स्टेशन पर ट्रेन और कोच इंडिकेशन बोर्ड, एक्सलेटर, लिफ्ट लगाने के साथ-साथ यात्री सुविधाओं आदि की समीक्षा की जायेगी। स्टेशन के उत्तर और दक्षिण में सर्कुलेटिंग एरिया में लगने वाली गड़ियों, पार्किंग आदि से होने वाली परेशानियों की भी शीघ्र समीक्षा की जायेगी। साउथ बिहार एक्सप्रेस,

पटना-पूना, संघमित्रा और दानापुर हावड़ा एक्सप्रेस को राजेन्द्रनगर टर्मिनल से चलाने से यात्रियों को हो रही परेशानियों पर डीआरएम ने कहा कि इसकी भी समीक्षा की जाएगी। (राष्ट्रीय सहारा, 19.10.2017)

बिहार में हर घर रसोई गैस योजना

केन्द्र सरकार जल्द ही 100 फीसदी घरों को रसोई गैस से जोड़ने के लिए बिहार में एक पायलट परियोजना शुरू कर सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बाबत केंद्र सरकार से खास अपील की है। राज्य सरकार इसके लिए केरोसिन तेल के अपने कोटे में भी कटौती को तैयार है।

इस महीने के शुरुआत में मुख्यमंत्री और केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच मुलाकात हुई थी। इस दौरान राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के साथ-साथ इससे ऊपर रहने वाले परिवारों को भी रसोई गैस से जोड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा था, 'फिलहाल सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना, 2011 के आधार पर केन्द्र सरकार की 'उज्ज्वला' योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रसोई गैस का कनेक्शन देती है। हमने इस बारे में सभी परिवारों को गैस कनेक्शन देने पर विचार करने को कहा है। केन्द्र सरकार भी इसके लिए तैयार है। उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में प्रायोगिक परियोजना के लिए राज्य के एक जिले का चयन किया जा सकता है।'

तेल कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बीते एक साल में 26-27 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया है। राज्य के लगभग 50 फीसदी परिवारों के पास ही इस वक्त रसोई गैस है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर करीब तीन-चौथाई परिवारों के पास गैस कनेक्शन है। इसीलिए अभी बिहार में रसोई गैस के मामले में अभी लंबा रास्ता तय करना है। अधिकारियों के मुताबिक अगर केन्द्र सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्ताव को मान लेती है, तो इससे इस अंतर को पाटने में काफी मदद मिलेगी। (बिज़नेस स्टैंडर्ड, 13.10.2017)

पीएम का निर्देश, बोधगया व गया का जल्द करें विकास

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/12 धार्मिक स्थलों के विकास के लिए केन्द्र ने शुरू की हृदय योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गया-बोधगया के विकास की योजनाओं को जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को इस संबंध में आदेश दिया। देश के 12 धार्मिक स्थलों के विकास के लिए केन्द्र ने हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्युमेंटेशन योजना (हृदय) शुरू की है। इसमें गया भी चयनित है।

मुख्य सचिव ने बताया कि गया में ब्रह्म सरोवर, वैतरणी और अक्षयवट मंदिर के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है। विष्णुपद और डूंगेश्वरी हिल से महाबोधि मंदिर तक के विकास की योजना जल्द शुरू हो जाएगी। इस पर प्रधानमंत्री ने बिहार में काम में तेजी लाने के लिए कहा। योजना के तहत इन शहरों में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास कर प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा। इन शहरों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। शहरों की मूलभूत सुविधाओं में विकास के साथ समुदाय के जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा। सुरक्षा और सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। योजना का पूरा खर्च केन्द्र सरकार वहन कर रही है। फिलहाल 12 शहरों के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें गया के लिए 40 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

बधाई

चैम्बर के सदस्य श्री गोविन्द कानोडिया, अधिवक्ता, बिहार युवा अधिवक्ता कल्याण समिति, पटना के राज्य कार्य समिति के सत्र 2017-2019 हेतु पटना प्रमंडलीय क्षेत्र के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। चैम्बर की ओर से श्री कानोडिया को बधाई।

हृदय योजना में चयनित शहर : हृदय योजना के तहत देश के 12 शहरों का चयन किया गया है। इनमें अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बदामी, द्वारिका, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, बनारस, वेलाकनी, वारंगल और गया शामिल हैं।

नि:शक्तों के लिए सुविधाओं का विकास : प्रधानमंत्री ने राज्य के सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों में नि:शक्तों के लिए सुविधाओं का विकास करने को कहा है। ऐसे लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में लो-फ्लोरिंग बसों का परिचालन करने को भी कहा गया है।

राज्य सरकार बना रही पर्यटन रोडमैप

पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर्यटन रोडमैप बना रही है। सभी सांसद और विधायक से उनके क्षेत्र में पड़ने वाले पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी मांगी गई है। वह विश्व पर्यटन दिवस पर होटल कौटिल्य विहार में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है, जो अपनी सांस्कृतिक पहचान को सहेजते हुए सांस्कृतिक ग्राम का निर्माण करा रहा है।

दीघा के पास विद्यापति नगर में बनेगा गाँधी टावर : मंत्री ने कहा कि राजधानी में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के पटना प्रवास की स्मृति में गाँधी टावर का निर्माण किया जाएगा। गाँधी जी दीघा के पास विद्यापति नगर में ठहरे थे, वहीं यह टावर बनेगा। इसका प्राक्कलन बन गया है। जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। टावर पर सभी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का नाम अंकित किया जाएगा।

(साभार : दैनिक भास्कर, 28.9.2017)

50 लाख कामगारों को मिलेगा लाभ

राज्य का छह दशक पुराना बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम पूरी तरह बदलने वाला है। इससे 50 लाख से अधिक कामगारों को लाभ होगा। उनकी सेवा शर्तों में व्यापक सुधार किया जा रहा है। कामगारों का वेतन अब सीधे और नियमित उनके बैंक खाते में जायेंगे। नये अधिनियम में सप्ताह में एक दिन अवकाश के साथ-साथ साल में 12 अलग से अवकाश मिलेंगे। चिकित्सा के दौरान कामगारों को सवैतनिक अवकाश नियोजकों को देना होगा। कार्यस्थल पर कामगारों को आवश्यक नागरिक सुविधा और सुरक्षा का इंतजाम करना होगा। रात्रि में काम करने वाली महिलाकर्मी को लाने व पहुँचाने की व्यवस्था नियोजक को करनी होगी। प्रतिष्ठानों को अब निबंधन के बाद अब एलआइएन नंबर मिलेगा कार्यस्थल पर नागरिक सुविधा बढ़ने से उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे।

(विस्तृत : प्रभात खबर 28.09.2017)

नौकरी बदलते ही पीएफ अकाउंट हो जायेगा ट्रांसफर

प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए पीएफ अकाउंट के ट्रांसफर को लेकर हमेशा टेंशन रहती है। लेकिन अब ये टेंशन दूर होने वाली है। अब नौकरी बदलते ही पीएफ अकाउंट खुद-ब-खुद ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऑटो पीएफ ट्रांसफर सुविधा कर दी गई है। ईपीएफओ ने फैसला प्राइवेट कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए लिया है। नई जगह नौकरी बदलने के बाद पीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना होगा। (विस्तृत : आज, 11.10.2017)

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296